आकाशवाणी देहरादून (उत्तराखण्ड)

बुधवार 29.10.2025 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025–26 के लिए उर्वरकों पर करीब 38 हजार करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी; मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य शर्तों को भी स्वीकृति दी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के लिये छियहत्तर करोड़ रुपए से अधिक की छह विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
- उत्तराखंड स्थापना के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर में रजत जयंती समारोह के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे; तैयारियां जोरों पर।
- गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने विकास भवन सभागार, पौड़ी में आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

केंद्रीय मंत्रिमण्डल मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य–सचिव होंगे। सरकार ने इस वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच तथा सिफ़ारिश करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025–26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्वीकृति दी है।

लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के लिये छियहत्तर करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित और स्वीकृत छह विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री, अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा–अर्चना कर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने जागेश्वर धाम परिसर का निरीक्षण कर मास्टरप्लान की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि जागेश्वर जनता की आस्था का केंद्र है और इसे दिव्य व भव्य स्वरूप देने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने वृद्ध जागेश्वर को भी जागेश्वर धाम के साथ विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जागेश्वर धाम को न केवल धार्मिक, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से भी वैश्विक पहचान मिले। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर प्राप्त होंगे।

समीक्षा बैठक

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ''लखपति दीदी योजना'' की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि लखपति दीदी योजना से जुड़ी गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाए और लाभार्थी महिलाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उन्होंने बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता, साफ–सफाई और पैकिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने और सिंघाड़ा, कमल ककड़ी, मशरूम व पर्ल कल्चर जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए ताकि महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके।

मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर हाईवे किनारे महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऑर्गेनिक उत्पाद, दालें, सरसों का तेल और सब्जियों की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने महिलाओं को घर से काम करने के अवसर देने के लिए क्लाउड किचन की शुरुआत करने के निर्देश दिए और एक वर्ष में 25 क्लाउड किचन खोलने का लक्ष्य रखा।

रजत जयंती समारोह

उत्तराखंड, नौ नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस अवसर पर एक से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में रजत जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। सचिव धर्मस्व एवं संस्कृति युगल किशोर पंत ने बताया कि समारोह में हर दिन अलग–अलग विषयों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनका उद्देश्य उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, संगीत, नृत्य और परंपराओं को प्रदर्शित करना है।

उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को लोकनृत्य, जागर गायन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। 2 से 8 नवंबर तक प्रतिदिन पूर्वाह्न, अपराह्न और सांय तीन सत्रों में लोकनृत्य, लोकगायन, नाट्य मंचन, पैनल डिस्कशन, शास्त्रीय संगीत और कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें उत्तराखंड के साथ हिमाचल, असम, जम्मू–कश्मीर, नागालैंड और भूटान जैसे राज्यों के कलाकार भी शामिल होंगे। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर रजत जयंती समारोह का समापन उत्तराखंड की विविध लोकसंस्कृतियों की प्रस्तुति और भूटान बैण्ड "मिस्टी टेरिस" के कार्यक्रम के साथ होगा।

रजत जयंती समारोह

उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के अवसर पर राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम में राज्य के स्थापना संग्राम की झलक, लोक संस्कृति की झंकार और आधुनिक विकास की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी। उन्होंने सभी सेक्टरों के लिए प्रभारी अधिकारी नामित करने, पुलिस व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और कार्यक्रम स्थल पर पंडाल, स्टेज, वीआईपी व आमजन के बैठने, पार्किंग, पेयजल व अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से कार्यक्रम स्थलों का डिजाइन व लेआउट तैयार कर उसका सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने को कहा। साथ ही, अन्य जिलों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।

आपदा राहत और पुनःनिर्माण

गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने विकास भवन सभागार, पौड़ी में आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताते हुए सभी विभागों को मरम्मत और स्थायी पुनर्निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 62 लाख रुपए की राहत राशि पात्र लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। आयुक्त ने कहा कि जिन परिवारों के मकान आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके विस्थापन के लिए वैकल्पिक स्थलों का चयन कर लिया गया है और भूगर्भीय विभाग को उनकी उपयुक्तता की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सड़कों, बिजली, पानी और विद्यालयों जैसी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री संवाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह कल पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों और आईटीबीपी जवानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा और सीमाओं की सुरक्षा ही उत्तराखंड की पहचान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे और उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सरकार सीमांत अंचलों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी की 14वीं बटालियन, मुनस्यारी पोस्ट का निरीक्षण किया और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा उनके अनुशासन और समर्पण पर टिकी है।

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से भी मुलाकात की तथा क्षेत्र की विकास योजनाओं और जनसमस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर :-

आठवें वेतन आयोग की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता हैं– आठवें वेतन आयोग पर बढे कदम, कैबिनेट ने दी सेवा शर्तो को मंजूरी, एक जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें। वहीं इसी ख़बर पर अमर उजाला की सुर्खी है – आठवां केंद्रीय वेतन आयोग एक जनवरी से होगा लागू 50 लाख कर्मचारियों व 69 लाख पेंशनरों को लाभ।

उत्तराखंड में बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सहारा लिखता हैं– वित्तीय प्रबंधन में देश के अव्वल राज्यों में उत्तराखंड। दैनिक जागरण ने लिखा है– वित्तीय प्रबंधन में धामी सरकार की देश में धमक।

देहरादून– टनकपुर एक्सप्रेस की आवृत्ति बढाने के प्रस्ताव को मंजूरी पर नवोदय टाइम्स लिखता हैं– उत्तराखंड को रेल मंत्रालय की बडी सौगात।